मध्य प्रदेश को सीमेंट का कोटा

5943. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सीमेंट के कोटे में 18 प्रतिशत कटौती करके उसे गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकारों को दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के लिये निर्धारित सीमेंट का कोटा पहले ही राज्य की मांग से कम था और उसमें और कटौती करने से मध्य प्रदेश के निर्माण कार्य रुक जायेंगे और वर्ष के इन दिनों में सीमेंट न मिलने से नागरिकों को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुन: विचार करेगी और मध्य प्रदेश के सीमेंट के कोटे में की गई कटौती को फिर पूरा कर दिया जायेगा; और यदि हां तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). 1976 में राज्य कोटे के अधीन मध्य प्रदेश राज्य को सीमेंट की खपत लगभग 6.94 लाख मीट्रिक टन अथवा 1.73 लाख मीट्रिक टन प्रति तिमाही थी । राज्य ने अप्रैल से जून, 1977 की तिमाही के लिए 2 लाख मीट्रिक टन के कोटे की मांग की थी । कई राज्यों में विद्युत् कटौतियां लागू किए जाने के कारण उत्पादन में हुई कमी को बराबरी से बांटने हेतु उक्त तिमाही में राज्यों के कोटे में 18 प्रतिशत की कटौती समान रूप से लागू करनी पड़ी । विगत तिमाहियों में लगाई जा चुकी कटौतियों को वापिस लेना सम्भव नहीं है । जैसे ही सीमेंट के उत्पादन की स्थिति में सुधार होगा कटौतियों को क्रमश: वापिस ले लिया जायेगा । वर्तमान तिमाही (जुलाई से सितम्बर) की अवधि में कटौती 18 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत की जा चुकी है ।

Light Houses in Ports

5944. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are constructing light houses in Ports; and

(b) if so, the names of the ports?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Government of India is responsible for the constructions, maintenance and up-keep of the "General" lighthouses and the coast line of India. The general lighthouses are under construction at the following Ports:-

(1) Kalingapatnam
(2) Krishnapatnam
(3) Pondicherry
(4) Kilakarai
(5) Tuticorin (Hare Island)
(6) Cochin
(7) Beypore
(8) Marmugao (Sao George)
(9) Umbergaon
(10) Little Andamans

2. Construction of "General" Lighthouses at Kasargod, Poneni and Bedi Port had also been sanctioned and construction work will be taken up as soon as land becomes available at these places.

"कोल जाति"

5945. **श्रीमती कमला बहुगुणा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोल जाति के सभी लोगों को आदिवासी घोषित कर दिया गया है परन्तु उनसे भी बदतर जिन्दगी बिताने वाले बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के कोलों को अभी तक आदिवासी घोषित नहीं किया गया; और

(ख) क्या कोल आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों को अब तक उपलब्ध संवैधानिक संरक्षण समाप्त कर देने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सारे मध्य प्रदेश राज्य में कोल समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में और सारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांवों में बिजली लगाया जाना

5946. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अब तक कितने गांवों में बिजली उपलब्ध कराई गई है;

(ख) वर्ष 1977–78 के लिए ऐसे कुल कितने गांवों को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या पौड़ी गढ़वाल जिले में, जहां बहुत कम गांवों में बिजली उपलब्ध कराई गई है, विद्युतीकरण कार्य को प्राथमिकता दिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तर काशी, चमौली, पौढ़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल नामक 8 जिले हैं । इन जिलों के 15,010 गांवों में से 31 मार्च, 1977 तक, 2,283 गांवों को विद्युतीकरण किया जा चुका था ।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड का कार्यक्रम 1977-78 के दौरान 730 और ऐसे गांवों को विद्युतीकृत करने का है ।

(ग) और (घ) पौढ़ी गढ़वाल जिले के 3,236 गांवों में से 31 मार्च, 1977 तक 327 (10 प्रतिशत) गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका था । राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1977-78 के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम में इस जिले के 125 और गांवों का विद्युतीकरण शामिल है ।

Development of Solar Energy Powered Grain Dryer

5947. DR. HENRY AUSTIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether National Industrial Development Corporation had developed India's first solar energy powered grain dryer which can dry a minimum of 10 tonnes of grain in a day at a cost of Rs. 6 per tonne;

(b) if so, the facts thereof;

(c) whether the NIDC also plans to make solar energy devices for agricultural and industrial products; and

(d) if so, the details thereof?